संख्या- 29 /2018//305/22-4-18-48(16)/14-1

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 21 मार्च, 2018

विषय- जिला कारागार, गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7988/नम-3/04/मुला0 शौ0/2017, दिनांक 05 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश की 24 कारागारों में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-73/2016/637/22-4-16-48(16)/14-1, दिनांक 13.06.2016 द्वारा रू0 385.44 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 192.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें जिला कारागार, गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक के निर्माण कार्य की रू0 16.06 लाख की प्रशासकीय एवं रू0 8.03 लाख की वित्तीय स्वीकृति भी सम्मिलित है तथा शासनादेश दिनांक 12.10.2017 द्वारा रू0 7.24 लाख अर्थात कुल रू0 15.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार गाजीपुर में मुलाकातियों के लिए विजिटर टॉयलेट ब्लाक (04 नग पुरूष शौचालय, 04 नग यूरिनल, 02 नग महिला शौचालय, 01 नग सैफ्टिक टैंक सोकपिट, 01 नग इण्डिया हैण्डपम्प तथा 01 नग सबमर्सिबिल बोरिंग टॉयलेट) का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 79,000/-(रूपया उन्नयासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्निलखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
(3) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।
(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जाय।
(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिए जायं।

4- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 13.06.2016 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पूर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या- 29/2018/305(1)/22-4-18-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी गाजीपुर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in